आई.एल.आर पी 1अनजब और हरियाणा(1971)1

नागरिक विविध

न्यायमूर्ति प्रेम चंद पंडित के समक्ष

महा सिंह,-याचिकाकर्ता।
बनाम
मांगे और अन्य-प्रतिवादी।

Civi] Mise. No. 211/C of 1969
in R.S.A. 1527 of 1968

29 अगस्त 1969.

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5) - धारा 153 - मृत व्यक्ति के खिलाफ अपील प्रस्तुत - पार्टियों के ज्ञापन में संशोधन - क्या अनुमति दी जा सकती है - निर्णय और डिक्री-शीट की प्रमाणित प्रति में नामों का गलत उल्लेख - द्वारा की गई गलती अपीलकर्ता ने उसमें उल्लिखित व्यक्ति के विरुद्ध अपील दायर करने में - ऐसी गलती - चाहे वह प्रामाणिक हो।

*अभिनिर्धारित किया गया कि ,*यदि किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अपील प्रस्तुत की जाती है जो प्रस्तुति की तारीख पर मर चुका है, तो न्यायालय संहिता की धारा 153 के तहत कारण शीर्षक में संशोधन की अनुमति दे सकता है या अपील ज्ञापन को संशोधन और प्रतिनिधित्व के लिए वापस कर सकता है। यद्यपि गलत व्यक्ति को प्रतिवादी के रूप में नामित किए जाने के कारण अपील अक्षम हो सकती है, लेकिन जो न्यायालय इससे निपटता है वह एक मुकदमे की कार्यवाही में कार्य कर रहा है और इस प्रकार अपील ज्ञापन में संशोधन का निर्देश देने के लिए धारा 153 के तहत पूरी शक्ति है। (पैरा 8)¬¬¬

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि निचली अदालत के फैसले और डिक्री-शीट की प्रमाणित प्रति में नामों के गलत उल्लेख के कारण अपील के पक्षकारों के नामों में कोई गलती होती है, तो यह गलती किसी घोर लापरवाही या उचित कमी के कारण नहीं हुई है। परिश्रम अपीलकर्ता या उसके एजेंट के लिए जिम्मेदार है, लेकिन प्रामाणिक है। यदि अपीलकर्ता अपील में पार्टियों के ज्ञापन में संशोधन के लिए आवेदन करता है, तो न्यायालय के विवेक का उपयोग संहिता की धारा 153 के तहत संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति देने के पक्ष में किया जाना चाहिए। (पैरा 9)¬

आवेदन आदेश 22, नियम 4 को धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ पढ़ा जाए, *के तहत* जिसमें प्रार्थना की गई है कि मुसादी मृतक का नाम हटा दिया जाए और उत्तरदाताओं 4 और 5 और लची राम और मन भारी को उनके उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में रिकॉर्ड पर लाया जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील पी.एस जैन और वी.एम जैन।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता जे.के शर्मा और के.जी भगत।

निर्णय

न्यायमूर्ति पीसी पंडित, - अपीलकर्ता द्वारा दायर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 22, नियम 4 के तहत इस आवेदन का निपटान करने के लिए, कुछ तथ्य बताए जा सकते हैं।चाय चंदगी, प्रतिवादी संख्या 1, ने मांगे और अन्य, प्रतिवादी संख्या 2 से 7, जो उनके सहयोगी थे, के खिलाफ स्वामित्व के आधार पर कृषि भूमि पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। उस मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, चंदगी ने 7 फरवरी, 1964 को उसी जमीन को उन प्रतिवादियों के पक्ष में उपहार में दे दिया। 29 फरवरी, 1964 को, उपहार-विलेख के आधार पर, चंदगी द्वारा दायर मुकदमे में समझौता कर लिया गया और खारिज कर दिया गया। सितंबर, 1964 में चंदगी के बेटे महा सिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें प्रथा के तहत घोषणा की गई कि उपहार, दिनांक 7 फरवरी, 1964, और समझौते के आधार पर पारित डिक्री, दिनांक 29फरवरी, 1964 उनके पिता चंदगी की मृत्यु के बाद उनके प्रत्यावर्ती अधिकारों के विरुद्ध शून्य और अप्रभावी थे। ट्रायल कोर्ट ने 1 अक्टूबर, 1966 को मुकदमे का फैसला सुनाया।¬¬

(2) नवंबर, 1966 में, उस डिक्री के खिलाफ मुस्सदी, प्रतिवादी नंबर 4 सहित प्रतिवादी नंबर 2 से 7 द्वारा विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक के समक्ष एक अपील दायर की गई थी। उस अपील के लंबित रहने के दौरान, 26 जनवरी, 1968 को मुसादी की मृत्यु हो गई, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा उसकी कानूनी सजा लाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिकॉर्ड पर प्रतिनिधि मुस्सदी की मृत्यु से अनभिज्ञता जताते हुए अपर जिला न्यायाधीश ने 3 अप्रैल 1968 को अपील स्वीकार कर ली।

(3) 19 जुलाई, 1968 को, चंदगी के बेटे महा सिंह द्वारा विद्वान अतिरिक्त जिला

न्यायाधीश, रोहतक के फैसले के खिलाफ इस अदालत में एक नियमित दूसरी अपील (संख्या 1527 का 1968) दायर की गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को उक्त अपील में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। चूंकि मुसादी का नाम निचली अपीलीय अदालत के फैसले की प्रमाणित प्रति और डिक्री-शीट में दर्ज किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता ने इस अदालत में प्रतिवादी नंबर 3 के रूप में अपना नाम भी शामिल किया।

(4) उपरोक्त अपील के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय में, वर्तमान आवेदन (सिविल विविध संख्या 211-सी, 1969) अपीलकर्ता के वकील द्वारा आदेश 22, नियम 4 और धारा 151, सीपीसी के तहत किया गया था, यह था इसमें कहा गया है कि मुस्सदी, प्रतिवादी संख्या 3, की मृत्यु 26 जनवरी, 1968 को हो गई, जब प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा दायर अपील अभी भी विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक की अदालत में लंबित थी। इस तथ्य के बावजूद कि मृतक मुसादी के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था, विद्वान न्यायाधीश ने उक्त अपील स्वीकार कर ली। मुसादी के कानूनी प्रतिनिधियों के गैर-पक्षपात के परिणामस्वरूप, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष उत्तरदाताओं संख्या 1 से 6 द्वारा दायर अपील समाप्त हो गई औ बर्खास्त कर दिया गया मृतक मुस्सदी अपने पीछे चार कानूनी प्रतिनिधि छोड़ गए, जिनमें से उनके बेटे मामन और चंदर, प्रतिवादी संख्या 4 और 5, पहले से ही रिकॉर्ड में थे। बाकी दो पुत्र उसके थे¬ लोही राम अौर विधवा मन भारी कानूनी प्रतिनिधियों को पहले रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था, क्योंकि मुसादी का नाम निचली अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री-शीट की प्रतियों में दिखाई दिया था। उस गलती के कारण अपीलकर्ता पहले वर्तमान आवेदन नहीं कर सका। यह प्रार्थना की गई कि न्याय के हित में, प्रतिवादी नंबर 3, मुस्सदी का नाम पार्टियों के नाम के मेमो से हटा दिया जाए और उसके उत्तराधिकारियों के नाम उसके कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में रिकॉर्ड पर लाए जाएं। इस आवेदन की सूचना उत्तरदाताओं के वकील को दी गई थी जो मेरे समक्ष उपस्थित हुए थे और इसमें की गई प्रार्थना का विरोध किया था।

(5) लीन लर्नेड ने 10 प्रतिवादियों के लिए परामर्श दिया, क्या इनोती अपीलकर्ताओं द्वारा लगाए

गए आरोप का खंडन करने में सक्षम है कि मुसादी की मृत्यु 26 जनवरी, 1968 को हुई थी, और इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि अपीलकर्ता द्वारा दी गई मृत्यु की तारीख सही थी। इसका मतलब यह है कि इस अदालत में वर्तमान दूसरी अपील दायर होने से बहुत पहले मुसादी की मृत्यु हो गई थी और फिर भी उसे प्रतिवादी नंबर 3 के रूप में शामिल किया गया था। यह निर्विवाद है कि किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है। आईबी भी उतना ही सच है कि यदि अपील की शुरुआत की तारीख पर उत्तरदाताओं में से एक की मृत्यु हो गई थी, तो उक्त अपील को अकेले उस आधार पर अन्य उत्तरदाताओं के खिलाफ खारिज नहीं किया जा सकता था। हालाँकि, यह निर्धारित करना होगा कि कानूनी नियम के अभाव में अपील आगे बढ़ सकती है या नहीं। मृत प्रतिवादी के प्रतिनिधि यदि अपीलकर्ता ने मुसादी के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवेदन नहीं किया था, तो उत्तरदाता अदालत से पार्टियों के नाम के ज्ञापन से उसका नाम हटाने के लिए कह सकते थे और फिर तय कर सकते थे कि अपील की अनुपस्थिति में सुनवाई और निर्धारण किया जा सकता है या नहीं। उसके कानूनी प्रतिनिधियों की. हालाँकि, मौजूदा मामले में, उस उद्देश्य के लिए एक आवेदन किया गया है और उसमें बताया गया है कि गलती कैसे हुई। अपीलकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार यह अपीलकर्ता की ओर से एक वास्तविक गलती थी, क्योंकि मुसादी का नाम फैसले की प्रमाणित प्रतियों और निचली अपीलीय अदालत की डिक्री-शीट में दिखाई देता रहा। वह गलती स्वयं प्रतिवादियों की लापरवाही के कारण थी क्योंकि वे निचली अपीलीय अदालत के समक्ष अपीलकर्ता थे और इस तथ्य के बावजूद कि उनके सह-अपीलकर्ता मुसादी की उस अदालत के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी, उन्होंने उसे कानूनी पक्ष में नहीं रखा था। प्रतिनिधि रिकॉर्ड पर थे और इसलिए, उनका नाम पार्टियों के नाम के ज्ञापन में दिखाया जाता रहा।¬

(6) अब सवाल यह उठता है कि क्या मुस्सदी के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए या नहीं और यदि हां, तो कानून के किस प्रावधान के तहत?¬

(7) अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह स्वीकार किया गया कि आदेश 22, नियम 4, सिविल प्रक्रिया संहिता, लागू नहीं होगा। हालाँकि, उन्होंने अपने आवेदन के समर्थन में तीन उच्च न्यायालयों, यानी मद्रास, उड़ीसा और मैसूर के फैसलों का हवाला दिया। उन अधिकारियों के आधार पर, उन्होंने प्रस्तुत किया कि कानूनी प्रतिनिधिमौजूदा मामले में मुसादी को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 153 के तहत पक्षकार बनाया जाना चाहिए। (अडुसुमिल्ली) गोपालकृष्णय्या और अन्य बनाम आदिवासी दक्ष्मना राव, (1) में मद्रास उच्च न्यायालय की एएफ 'उल खंडपीठ ने इस प्रकार कहा:

> "यदि किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अपील प्रस्तुत की जाती है जो प्रस्तुति की तारीख पर मर चुका है, तो न्यायालय धारा 153 के तहत कारण शीर्षक में संशोधन की अनुमति दे सकता है या अपील ज्ञापन को संशोधन और प्रतिनिधित्व के लिए वापस कर सकता है। हालाँकि गलत व्यक्ति को प्रतिवादी के रूप में नामित किए जाने के कारण अपील अक्षम हो सकती है, लेकिन जो अदालत इससे निपटती है वह एक मुकदमे में कार्यवाही कर रही है और इस तरह अपील ज्ञापन में संशोधन का निर्देश देने के लिए धारा 153 (सीपीसी) के तहत पूरी शक्ति है। ।"

(8) महान प्रसाद सिंह देव बनाम गणेश प्रसाद भगत और अन्य, (2) में उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा-

> "एक बंधक डिक्री के बाद डिक्री-धारकों में से एक L की मृत्यु हो गई और उसकी बेटी के को एक गर्म प्रतियोगिता के बाद L के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। डिक्री के निष्पादन में निर्णय-ऋणी ने धारा 47, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आपत्ति दायर की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया और निर्णय-ऋणी ने बर्खास्तगी के

खिलाफ अपील दायर की। हालाँकि, अपीलकर्ता ने डिक्री-धारकों में से एक R को प्रतिवादी के रूप में शामिल करना छोड़ दिया और अपील के ज्ञापन में L को उत्तरदाताओं में से एक के रूप में दिखाया गया, K को नहीं। लंबे समय के बाद कारण शीर्षक में संशोधन के लिए एक आवेदन किया गया था आर और K को प्रतिवादी के रूप में शामिल करके और देरी को माफ करने के लिए अपील का ज्ञापन। निर्णय की प्रमाणित प्रति और डिक्रीटल आदेश जिसके विरुद्ध¬

(1) AXR. 1925 मैड. 1210.
(2) ए.आई.आर 1952 उड़ीसा 188।

जो अपील दायर की जानी थी उसमें "और अन्य" जोड़ने के साथ पहले को छोड़कर उत्तरदाताओं के नाम शामिल नहीं थे और निष्पादन याचिका की निजी प्रति जिस पर अपील दायर करते समय अपीलकर्ता के वकील ने कार्रवाई की थी वह स्वयं गलत थी जहाँ तक इसने H को डिक्री-धारक के रूप में दिखाना बिल्कुल ही छोड़ दिया और K का प्रतिस्थापित नाम दिखाए बिना L को डिक्री-धारक के रूप में दिखाना जारी रखा:

माना गया: मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह गलती ऋणी या उसके एजेंट की किसी बड़ी लापरवाही या उचित परिश्रम की कमी के कारण नहीं हुई थी। हालाँकि गलती कुछ हद तक वकील की ओर से पर्याप्त व्यक्तिगत जाँच की कमी के कारण हुई थी, लेकिन यह ऐसी नहीं थी कि अपीलकर्ता को कारण शीर्षक में संशोधन की मांग करने में देरी की माफ़ी पाने से वंचित किया जा सके। धारा 153 सीपीसी के तहत संशोधन की प्रार्थना की अनुमति देने के पक्ष में न्यायालय के विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए।¬

(10) डोड्डामल्लप्पा चन्नबसप्पा कारी बनाम गंगाप्पाक्स शिदप्पा गुलगंजी और अन्य (3) में, *न्यायमूर्ति* एम. सदाशिवय्या, ने देखा-

> "सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 153 के प्रावधान व्यक्ति के खिलाफ दायर अपील पर लागू होंगे।" वह व्यक्ति जो उस अपील के शुरू होने के समय मर गया था और अदालत अपीलकर्ता (प्रतिवादी) को अपील के ज्ञापन में संशोधन करने की अनुमति दे सकती है ताकि मूल वादी के कानूनी प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर लाया जा सके जब वादी की मृत्यु हो गई थी। जिस समय अपील दायर की गई थी।"

(11) यह उल्लेख किया जा सकता है कि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने मेरे सामने स्वीकार किया कि वह उपर्युक्त प्राधिकारियों के विपरीत विचार करते हुए किसी भी फैसले पर अपना हाथ नहीं डाल सकते।¬

ए

मैं

(12) वर्तमान मामले में, मुझे लगता है कि अपीलकर्ता द्वारा की गई गलती वास्तविक थी, क्योंकि मुसादी का नाम निचली अपीलीय अदालत के फैसले और डिक्री-शीट की प्रमाणित प्रतियों में दिखाई देता रहा।

(3) ए.आई.आर 11962 मैसूर 4 44*मुचुअल फंड*नाथू बम रोशन लाल लूना बनाम पंजाब राज्य आदि (*न्यायमूर्ति* तुली,)

(13) मद्रास, उड़ीसा और मैसूर उच्च न्यायालयों के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा अपनाए गए विचार के बाद, मैं इस आवेदन को स्वीकार करूंगा और निर्देश दूंगा कि मृतक मुसादी का नाम रिकॉर्ड से हटा

दिया जाए और उसके स्थान पर उसके कानूनी प्रतिनिधियों के नाम रखे जाएं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 153जैसा कि ऊपर बताया गया है, दो कानूनी प्रतिनिधि पहले से ही रिकॉर्ड में हैं। शेष दो, लच्छी राम और मन भारी को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाए। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।¬

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ममता,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

रोहतक, हरियाणा।